भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2309

06 अगस्त, 2024 को उत्तर के लिए नियत

ई-वाहन पारिस्थितिकी तंत्र

2309. श्री सुरेश कुमार शेटकर:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इलेक्ट्रिक वाहन इकोसिस्टम के अंतर्गत विनिर्माण और चार्जिंग अवसंरचना को सहायता प्रदान करके ई-वाहन पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और सुदृढ़ीकरण करेगी, जिससे भुगतान सुरक्षा तंत्र के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के लिए ई-बसों को अधिक से अधिक अपनाने को प्रोत्साहित किया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है तथा इसके लिए कितनी धनराशि स्वीकृत/व्यय की गई है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा)

(क) और (ख): भारी उद्योग मंत्रालय ने देश में ई-बसों को अपनाने सहित इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित स्कीमें शुरू की हैं:-

i. इलेक्ट्रिक बसों सहित इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों (एक्सईवी) के अंगीकरण को बढ़ावा देने के लिए 2015 से भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (फ़ेम इंडिया) स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत लगभग 280 करोड़ रुपये की राजकीय प्रोत्साहन राशि से देश के विभिन्न शहरों में 425 इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड बसों को परिनियोजित किया गया था।

ii. कुल 11,500 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता से 1 अप्रैल, 2019 से पांच वर्ष की अवधि के लिए 2019 से भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (फेम इंडिया) स्कीम, चरण-II । फेम इंडिया स्कीम के इस चरण के अंतर्गत भारी उद्योग मंत्रालय ने लगभग 3009 करोड़ रुपये की राजकीय प्रोत्साहन राशि से 6862 इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी दी।

iii. इलेक्ट्रिक वाहनों और उनके घटकों सहित उन्नत ऑटोमोटिव उत्पादों के मामले में भारत की विनिर्माण क्षमताओं में वृद्धि करने के प्रयोजन से 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय से ऑटोमोबिल और ऑटो घटक उद्योग (पीएलआई-एएटी) के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम। इस स्कीम में इलेक्ट्रिक वाहनों की विभिन्न श्रेणियों यथा- ई-दुपहिया, ई-तिपहिया, ई-चौपहिया सहित ई-ट्रक और ई-बस के लिए भी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

*****